

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 179
सोमवार 21 जुलाई, 2025
30 आषाढ़, 1947 (शक)

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

179. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पाँच वर्षों के दौरान विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार विगत तीन वर्षों के दौरान घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने में सफल रही है और यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के नाम क्या हैं जिनका सरकार विनिवेश करने का विचार कर रही है और उससे कितनी राशि प्राप्त होने की संभावना है तथा सरकार ऐसे संगठनों से विनिवेश करने पर किन कारणों से विचार कर रही है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): विगत पांच वर्षों के लिए विनिवेश प्राप्तियों का संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्ति निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक प्राप्ति
2020-21	32,000	32,886
2021-22	78,000	13,534
2022-23	50,000	35,294
2023-24	विनिवेश प्राप्तियों के लिए कोई विशेष लक्ष्य नहीं है।	16,507
2024-25		10,163

वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान (आरई) से अलग विनिवेश लक्ष्यों को निर्धारित करने को रोक दिया गया है। यद्यपि, संशोधित अनुमान 2023-24, संशोधित अनुमान 2024-25 और बजट अनुमान 2025-26 के लिए विविध पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत क्रमशः 30,000 करोड़ रुपये, 33,000 करोड़ रुपये और 47,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिनमें विभिन्न तंत्रों के माध्यम से इक्विटी निवेशों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन से अनुमानित प्राप्तियां शामिल हैं।

(ख) एवं (ग): सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) में विनिवेश (i) विभिन्न सेबी-अनुमोदित पद्धतियों जैसे आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), बिक्री की पेशकश (ओएफएस), शेयरों की वापसखरीद आदि के माध्यम से अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री और (ii) रणनीतिक विनिवेश अर्थात् प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ एक रणनीतिक खरीदार को सरकारी शेयरधारिता की समग्र या पर्याप्त बिक्री के माध्यम से करती है।

रणनीतिक विनिवेश/निजीकरण की नीति इस आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार को उन क्षेत्रों में उपस्थिति कम कर देनी चाहिए, जिनमें प्रतिस्पर्धात्मक बाजार बहुत पहले से आए हुए हैं और पूंजी निवेश, तकनीकी उन्नयन और कुशल प्रबंधन परिपाटियों जैसे विभिन्न कारकों के कारण ऐसी इकाइयों की आर्थिक क्षमता रणनीतिक निवेशक के हाथों में संभवतः बेहतर रूप से अन्वेषित होगी। लाभप्रदता/हानि निजीकरण/रणनीतिक विनिवेश का प्रासंगिक मापदंड नहीं है। पिछले चार वर्षों के दौरान निम्नलिखित सीपीएसई का रणनीतिक विनिवेश किया गया।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सीपीएसई/इकाई का नाम	निजीकरण के समय लाभ/हानि
1	2021-22	एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एआईएक्सएल और एआईएसएटीएस (संयुक्त उद्यम)	घाटे में
2	2022-23	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)	घाटे में
3	2024-25	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल), एमएसटीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी	लाभ में

जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बैंकों का संबंध है, आईडीबीआई बैंक प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के अधीन है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/बैंकों के लिए, अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से विनिवेश, समय-समय पर प्रचलित बाजार परिस्थितियों के आधार पर, विभिन्न सेबी-अनुमोदित पद्धतियों के माध्यम से मूल्य को निर्मुक्त करने, जन स्वामित्व को बढ़ावा देने और उच्च स्तर की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम जन शेयरधारिता की शर्त को पूरा करने के लिए किया जाता है।

विनिवेश सौदा प्रशासनिक व्यवहार्यता, बाजार परिस्थितियों, आर्थिक दृष्टिकोण और निवेशक अभिरुचि पर निर्भर करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, चालू वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश से वास्तविक प्राप्तियों की मात्रा का पूर्वानुमान लगाना कठिन है।
